2026:AHC:212691

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT TAX No. - 4124 of 2026

M/S Kesarwani Traders

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Anarannaj Pratap Singh
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 53

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Anurag Pratap Singh, learned counsel for the petitioner and Shri Shashi Kant Mishra, learned Standing Counsel for the respondents.

2. A joint statement has been made by learned counsel for the rival parties that they do not propose to file any affidavit and the petition be decided on the basis of documents available on record.

3. With the consent of the parties, the petition is being decided at the fresh stage.

4. The case of the petitioner is that the petitioner happens to be a firm registered under the U.P. Goods and Services Tax Act, 2017. A show cause notice came to be issued on 20.12.2023 by the Assistant Commissioner, Commercial Tax Department, State Tax, Sector-5, Prayagraj, U.P. under Section 73(1) of the Act for the Financial Year 2018-19 in DRC-01 for demanding Rs. 5,91,64/- as tax, Rs. 4,97,18/- as interest and Rs. 20,000/- as penalty. It is also the case of the petitioner that though the show cause notice came to be issued on 20.12.2023, however, due to negligence of the Chartered Accountant and the Advocate, the petitioner could not present himself on the date of hearing and thereafter, a reminder came to be issued on 08.02.2024, scheduling the date of hearing on 23.02.2024. It is also the case of the petitioner that the show cause notice was transmitted in View Additional Notices and Orders section and as such the reply could not be filed. The second respondent proceeded to pass the assessment order creating a demand Rs.63,096/- as tax, Rs.56,692/- as interest and Rs.20,000/-

as penalty. The writ petitioner preferred an appeal against the said order before the appellate authority on 02.01.2026 along with delay condonation application, which came to be rejected by virtue of order dated 04.02.2026 passed by the Additional Commissioner, Grade-II (Appeal), Zone-1, State Tax, U.P., Prayagraj.

5. Questioning both the orders, the present petition has been preferred.

6. Learned counsel for the petitioner, as per instructions received from his client, is confining his relief at this juncture to the order dated 04.02.2026 passed by the respondent no. 3 dismissing the appeal on the ground of delay. It is contended that a specific ground disclosing the reasons for delay was taken but the same has not been considered and brushed aside.

7. Sri Shashikant Mishra, on the other hand, submits that though the appellate order is not happily worded, but admittedly there is a delay. However, according to him, propriety demanded that the order impugned ought to have been passed after considering the contention raised therein.

8. I have heard the counsel for the parties and perused the record carefully.

9. Apparently, an ex-parte order came to be passed on 16.04.2024 by the respondent no. 2, against which an appeal was preferred, which came to be rejected on 04.02.2026 on the ground of delay. The appeal came to be preferred by the petitioner on 02.01.2026 and the same was delayed by as many as 510 days, i.e. 17 months. In the delay condonation application accompanied with the appeal, the following was pleaded:-

"*1*-यह कि अपीलकर्ता का संगत वर्ष का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 16-04-2024 को पारित किया गया था जिसका आदेश पोर्टल पर परिलक्षित हो गया था परन्तु व्यापार दिनांक 12-02-2025 से सदैव के लिए बंद कर दिया था इसलिए कोई जानकारी नही हो सकी थी।

2-यह कि फर्म के मुख्य साझीदार सुनवायी की तिथि दिनांक 20-12-2023 को बीमार थे जिसके कारण वाद के सुनवाई की जानकारी नहीं हो सकी थी।

3-यह कि अपीलकर्ता को एकपक्षीय आदेश की जानकारी अमीन के द्वारा वसूली की कार्यवाही के दौरान हुई जिसके कारण निर्धारित अवधि में अपील दाखिल नही कर सका था जिसके कारण अपील दाखिल करने में देरी हो गयी जो परिस्थितियो को देखते हुए देरी क्षमा किये जाने योग्य है ।

4-यह कि अपीलकर्ता को माह जुलाई 2024 में अपील दाखिल कर देनी चाहिए थी जो माह दिसम्बर 2025 में दाखिल कर रहा है जिसके कारण अपील दाखिल करने में 18 माह की देरी हो गयी है जो जानबूझकर देरी नही

की गयी है जो क्षमा योग्य है ।

प्रार्थना

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि अपीलकर्ता के देरी क्षमा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके अपील दाखिल करने में हुई 18 माह की देरी क्षमा करके अपील पंजीकृत करने की कृपा करे।"

10. The appellate order is dated 04.02.2026, which reads as under :-

"अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) न्यायिक क्षेत्र-द्वितीय, राज्यकर, प्रयागराज

अपीलीय प्राधिकारी- प्रदीप कुमार सोनी, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील)-द्वितीय, रा० कर, प्रयागराज

अपील सं०- *AD0901260029328* वर्ष-2018-19. *UPGST/CGST ACT 2017* की धारा-73(9) के अन्तर्गत

Trade Name- *M/s KESARWANI TRADERS 920, CHANDAPUR KA HATA, MUTTHIGANJ,*
PRAYAGRAJ, ***GSTIN*** *09AAGFK8926M2ZL*

::- बनाम -::

सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-5, प्रयागराज।

::- निर्णय -::

प्रश्नगत अपील सं०- *AD0901260494334* दिनांक- 27/01/2026 सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-5, प्रयागराज द्वारा व्यापारी के वर्ष 2018-19, *Order No- ZD090424206242R Order Date- 16/04/2024, UPGST/CGST ACT 2017* की धारा-73(9) के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसमें सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. के अन्तर्गत (कर, अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड) रु० 139788.00 विवादित धनराशि अपीलकर्ता द्वारा मानी गयी है। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन अपील दिनांक 02/01/2026 को दाखिल की गयी, जो कि राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के प्राविधानो के अनुसार विलम्ब से दाखिल की गयी। अपीलकर्ता को नोटिस जारी कर दिनांक 27-01-2026, 31-1-2026 के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु नियत तिथि पर कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रश्नगत अपील के स्वीकारोक्ति के स्तर पर परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा विवादित आदेश- *ZD090424206242R* दिनांक 16/04/2024 को पारित किया गया है तथा इसकी तामीली अधिनियम की धारा-169(*c), (d)* में वर्णित व्यवस्था के क्रम में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गयी है। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल *APL-1* में भी *Date of Communication of the Order 16/04/2024* स्वीकार किया है। पारित विवादित आदेश के विरुद्ध व्यापारी द्वारा अपील 20 माह से अधिक समय बाद दाखिल की गयी है जो अधिनियम में दी गयी समय सीमा (3 माह) के बाहर है।

राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा-107 में अपील दाखिल हेतु निम्न

व्यवस्था दी गयी है :-

Section 107 (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act by an adjudicating authority may appeal to such Appellate Authority as may be prescribed within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.

Section 107(4) The Appellate Authority may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, as the case may be allow it to be presented within a further period of one month.

Rule 108(1)-- An appeal to the Appellate Authority under sub-section (1) of section 107 shall be filed in FORM GST APL-01, along with the relevant documents.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा-107 (1) में अनिवार्य रुप से आदेश (*Date of Communication of Order)* के विरुद्ध तीन महीने के अंदर अपील दाखिल करने की व्यवस्था है, जबकि अपीलकर्ता द्वारा अपील तीन माह बाद दाखिल की गयी है। वर्णित व्यवस्था के क्रम में अपील दाखिल नहीं की गयी है एवं विलम्ब से है।

इसी प्रकार अधिनियम की धारा-107(4) में एक माह का अतिरिक्त समय अपीलकर्ता को *Delay Condonation* हेतु पर्याप्त साक्ष्यों के साथ एवं *Appellate Authority* के *satisfaction* के आधार पर दिया गया है। वर्णित व्यवस्था के क्रम में अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील निर्धारित अवधि के 17 माह उपरान्त दाखिल की गई है जो विलम्ब से है एवं अधिनियम की धारा-107(4) के अंतर्गत स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत अपील राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के अंतर्गत दी गयी समय सीमा एवं प्राविधानों के अनुरुप दाखिल नहीं की गयी है।

उपरोक्त विवेचना के क्रम में अधिनियम की धारा-107 (1), 107(4) एवं नियम 108(1) में निहित प्राविधानों के क्रम में अपील दाखिल न करने पर स्वीकार (एडमिट) योग्य नहीं है।

//आदेश //

उपरोक्त विवेचना के क्रम में अपील सं० *AD0901260029328* दिनांक-02/01/2026 में अपीलकर्ता द्वारा अपील निर्धारित समय सीमा के उपरान्त 17 माह बाद विलम्ब से दाखिल की गयी है, जो कि राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा-107(1), 107(4) एवं नियम 108(1) के प्रावधानों के अनुरुप न होने के कारण प्रथमदृष्ट्या स्वीकार (एडमिट) किये जाने योग्य नहीं है। अत प्रश्नगत अपील संदर्भित प्रावधानों के अनुरूप न होने पर अस्वीकार की जाती है। आदेश की मूल प्रति अपीलीय पत्रावली पर सुरक्षित रखी जाये।

(प्रदीप कुमार सोनी)

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील)-द्वितीय

राज्य कर, प्रयागराज।"

11. A bare perusal of the order impugned would reveal that the same though is of two pages, but there is no consideration of the ground taken in the memo of appeal for condonation of delay, once a ground is taken, tenable or untenable in entirety, which has not been done. Since a statement has been made by the learned Standing Counsel that the matter may be remitted back, thus, without delving further into the issue, the petition is being decided in the following terms:-

(i) The order dated 04.02.2026 passed by Additional Commissioner, Grade-II (Appeal), Zone-1, State Tax, U.P., Prayagraj / third respondent is set aside.

(ii) The matter stands remitted back to the authority to consider the appeal including the delay condonation application and to pass orders in accordance with law within a period of two months.

12. Needless to point out that this Court has not gone into the merits of the matter and all questions are left open to be decided by the Appellate Authority.

13. With the aforesaid observations, the petition stands **disposed of**.

(Vikas Budhwar,J.)

October 9, 2026
N.S.Rathour

Digitally signed by :-
NIPENDRA SINGH RATHOUR
High Court of Judicature at Allahabad